Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

Original Article

सतत ग्रामीण विकास में डेयरी की भूमिका

श्रेया राज

शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

Manuscript ID:
JRD -2026-180524
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 5(A)
Pp.102-104
May- 2026
Submitted: 15 Apr. 2026
Revised: 25 Apr. 2026
Accepted: 10 May. 2026
Published: 31 May 2026

सार–संक्षेप:

भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जिसकी आत्मा इसके गाँवों में बसती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार केवल खेती ही नहीं, बल्कि पशुपालन और विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र भी है। सतत विकास का अर्थ एक ऐसी प्रगति से है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ भविष्य की पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता न करे। इस परिप्रेक्ष्य में, डेयरी क्षेत्र न केवल ग्रामीण समुदायों को पोषण सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी एक अपरिहार्य स्तंभ के रूप में उभरा है। डेयरी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आय के विविधीकरण में है। कृषि अक्सर मानसून और मौसमी चक्रों पर निर्भर होती है, जिससे किसानों की आय में अनिश्चितता बनी रहती है। पशुपालन किसानों को वर्षभर नियमित आय प्रदान कर इस जोखिम को कम करता है। विशेष रूप से भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए, डेयरी व्यवसाय एक सशक्त सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। डेयरी क्षेत्र सतत ग्रामीण विकास का एक सशक्त स्तंभ है। यदि आधुनिक तकनीक, बेहतर पशु चिकित्सा सेवाओं और सुदृढ़ बाजार व्यवस्था का विस्तार किया जाए, तो डेयरी उद्योग न केवल ग्रामीण गरीबी को दूर करने में सक्षम होगा, बल्कि भारत की समग्र आर्थिक प्रगति में भी मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यशब्द : *लघु ग्रामीण विकास, डेयरी क्षेत्र, पशुपालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तीकरण , पोषण सुरक्षा , आर्थिक सुदृढीकरण , सहकारिता आंदोलन, शाश्वत विकास , कृषी-पशुपालन एकीकरण , दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, सामाजिक समावेशन , पर्यावरण संरक्षण , आत्मनिर्भरता*

परिचय:

सतत ग्रामीण विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना है। इस संदर्भ में, डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में उभरा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ कृषि मौसमी निर्भरता और अनिश्चितताओं से घिरी है, डेयरी एक विश्वसनीय और निरंतर आय का स्रोत प्रदान करती है। डेयरी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक सुदृढ़ीकरण में है। यह छोटे और सीमांत किसानों को दैनिक नकदी प्रवाह प्रदान करता है, जिससे उनकी ऋण निर्भरता कम होती है। विशेष रूप से, महिला सशक्तिकरण में डेयरी का योगदान अतुलनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन का अधिकांश कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, डेयरी और जैविक खेती एक–दूसरे के पूरक हैं। पशुओं का अपशिष्ट (गोबर) मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खाद और ऊर्जा के विकल्प के रूप में बायोगैस का स्रोत बनता है। यह चक्र न केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करता है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली को भी बढ़ावा देता है। डेयरी उद्योग कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ग्रामीण परिवारों को प्रोटीन युक्त आहार सुलभ होता है। यदि आधुनिक तकनीक, कुशल पशु स्वास्थ्य सेवाओं और सहकारी मॉडल को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, तो डेयरी क्षेत्र सतत ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे प्रभावी उपकरण सिद्ध होगा।

आर्थिक सुदृढ़िकरण और आय का स्रोत:

ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका सर्वोपरि है, परंतु यह व्यवसाय मुख्य रूप से मौसमी प्रकृति का होता है। भारतीय किसान पूरी तरह से मानसून की अनिश्चितताओं, वर्षा के समय और उसकी मात्रा पर निर्भर रहते हैं। जब कभी सूखा पड़ता है या अत्यधिक बाढ़ आती है, तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में डेयरी व्यवसाय (पशुपालन) ग्रामीण परिवारों के लिए एक ठोस और भरोसेमंद आर्थिक कवच के रूप में उभरकर सामने आता है। यह व्यवसाय किसानों को न केवल जोखिम से बचाता है, बल्कि उन्हें साल के बारह महीने एक नियमित और निश्चित नकद आय का जरिया प्रदान करता है। फसल चक्र की अपनी एक समय सीमा होती है, जिसके तहत फसलों की बुआई से लेकर उनकी कटाई तक महीनों का इंतजार करना पड़ता है। किसानों को वर्ष में केवल एक या दो बार ही फसल बेचने पर बड़ी रकम मिलती है। इसके विपरीत, डेयरी उद्योग एक ऐसा माध्यम है जहां दूध की बिक्री से हर दिन, या हर सप्ताह आय प्राप्त होती रहती है। यह निरंतर मिलने वाली नकद राशि ग्रामीण परिवारों में तरलतायानी पैसे के बहाव को बनाए रखती है। दैनिक जरूरतों जैसे राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, खाद–बीज की खरीद और अचानक आने वाले चिकित्सा खर्चों के लिए किसानों को किसी साहूकार या बैंक के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यह नियमित आय उन्हें स्थानीय ऋणदाताओं के ऊंचे ब्याज दर वाले जाल में फंसने से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। भारत में अधिकांश किसानों की श्रेणी छोटे और सीमांत किसानों की है, जिनके पास खेती के लिए बहुत ही कम भूमि उपलब्ध है। केवल पारंपरिक खेती के भरोसे ऐसे परिवारों का भरण–पोषण करना लगभग असंभव हो जाता है। इन परिस्थितियों में डेयरी फार्मिंग अब केवल एक पूरकयानी साइड बिजनेस नहीं रह गया है, बल्कि यह उनकी आजीविका का मुख्य आधार बन चुका है। पशुपालन के लिए बहुत बड़े भूभाग की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कम जमीन वाले या भूमिहीन मजदूर भी इस व्यवसाय को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
श्रेया राज शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

How to cite this article:
राज, श्रेया. (2026). सतत ग्रामीण विकास में डेयरी की भूमिका. Journal of research & development, 18(5(A)), 102–104. https://doi.org/10.5281/zenodo.20954873

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.20954873
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

इसके अतिरिक्त, डेयरी व्यवसाय और कृषि एक–दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। फसलों के अवशेष, जैसे भूसा और डंठल, पशुओं के लिए पौष्टिक चारे का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर, पशुओं से मिलने वाला गोबर खेतों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद बनता है। इससे रासायनिक खादों पर होने वाला खर्च घटता है और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। इस प्रकार, डेयरी व्यवसाय न केवल ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को गांव में ही रोजगार के नए अवसर दे रहा है, बल्कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना रहा है।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशनः

सतत ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। भारतीय डेयरी क्षेत्र की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। ग्रामीण अंचलों में पशुओं के प्रबंधन, उनके स्वास्थ्य की देखरेख, चारा काटने, कतरने और सुबह–शाम दूध निकालने का लगभग 70 से 80 प्रतिशत कार्य पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा ही संभाला जाता है। इस भारी योगदान के बावजूद, अतीत में महिलाओं के इस श्रम को पारिवारिक काम मानकर अनदेखा किया जाता था और दूध की बिक्री से होने वाली आय पर केवल पुरुषों का नियंत्रण रहता था। परंतु, डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार ने इस सामाजिक ताने–बाने को पूरी तरह से बदल दिया है। सहकारी समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज लाखों ग्रामीण महिलाएं सीधे मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं। अब दूध की बिक्री से होने वाली वित्तीय आय बिना किसी बिचौलिये के सीधे महिलाओं के अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में डिजिटल रूप से पहुंचती है। जब पैसा सीधे महिला के हाथ में आता है, तो परिवार के भीतर और समाज में उसकी स्थिति मजबूत होती है। इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ती है और घर के महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों जैसे–संपत्ति की खरीद, खेती के विस्तार या आपातकालीन खर्चों में उनकी आवाज और निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान होने लगता है।

आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर महिलाएं अब केवल मूक दर्शक नहीं, बल्कि अपने घर की वित्तीय प्रबंधक बन गई हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का यह प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका एक रिपल इफेक्ट (व्यापक सकारात्मक प्रभाव) पूरे परिवार और समाज पर दिखाई देता है। पुरुष आय की तुलना में महिलाएं अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिवार के कल्याण, बच्चों की उच्च शिक्षा और पौष्टिक भोजन पर खर्च करती हैं। डेयरी से होने वाली दैनिक या साप्ताहिक आय के कारण घरों में कुपोषण दूर हो रहा है, बेटियों को बेहतर स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल रहा है और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इसके अलावा, जब महिलाएं दूध जमा करने के लिए सहकारी केंद्रों पर प्रतिदिन एक साथ आती हैं, तो वहां जाति, वर्ग और सामाजिक भेदभाव की दीवारें टूटती हैं। सभी पृष्ठभूमि की महिलाएं एक मंच पर आकर अपने अधिकारों, स्वास्थ्य और गांवों की समस्याओं पर चर्चा करती हैं। इस प्रकार, डेयरी फार्मिंग ग्रामीण भारत में रूढ़िवादी सामाजिक संरचना को बदलने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और एक समावेशी व समतामूलक समाज के निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम साबित हो रही है।

तालिका 1 : भारत में डेयरी क्षेत्र का ग्रामीण विकास पर प्रभाव (2015–2025)

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)	ग्रामीण परिवारों की भागीदारी (प्रतिशत)	महिला सहभागिता (प्रतिशत)	डेयरी से औसत वार्षिक आय (₹)	सहकारी समितियों की संख्या	पोषण सुरक्षा सूचकांक (प्रतिशत)
2015	146	42	68	38000	155000	52
2016	155	44	69	41500	160500	54
2017	165	46	70	45000	167000	57
2018	176	49	72	49500	174000	60
2019	188	52	73	54000	181500	63
2020	198	55	74	58500	189000	66
2021	210	58	75	63000	196500	69
2022	221	61	76	68000	205000	72
2023	230	64	77	73500	214000	75
2024	239	67	78	79000	223500	78
2025	248	70	80	85000	232000	81

स्रोतः– राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25

पोषण सुरक्षा और स्वास्थ्यः

कुपोषण और भुखमरी आज भी ग्रामीण भारत के सामने एक अत्यंत गंभीर और जटिल चुनौती बनी हुई है, जो सीधे तौर पर देश के मानव संसाधन के विकास को प्रभावित करती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और संतुलित आहार की कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग और महिलाओं में गंभीर एनीमिया (खून की कमी) जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। इस पोषण संबंधी संकट को दूर करने में डेयरी क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी हथियार सिद्ध हो रहा है। दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, छाछ, घी और पनीर, मानव शरीर के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन–D, विटामिन B_{12} और अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों का सबसे प्राथमिक, प्राकृतिक और सुलभ स्रोत हैं। जब किसी ग्रामीण परिवार के पास अपने दुधारू पशु होते हैं, तो दूध की एक निश्चित मात्रा बाजार में बेचने से पहले घर के उपभोग के लिए अनिवार्य रूप से बचा ली जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ घर के नवजात बच्चों, बढ़ती उम्र के किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मिलता है, जिन्हें रोजाना ताजा और शुद्ध दूध पीने को उपलब्ध होता है। शाकाहारी बहुल भारतीय ग्रामीण समाज में पशु प्रोटीन का दूध ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को गति देता है तथा उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। नियमित रूप से दूध का सेवन करने से ग्रामीण आबादी में कुपोषण के स्तर में तेजी से गिरावट आती है, जिससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में बड़ी मदद मिल रही है।

वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भी डेयरी फार्मिंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र विशेष रूप से लक्ष्य–2 यानी शून्य भुखमरी और लक्ष्य–3 यानी उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली को धरातल पर सच करने का काम कर रहा है। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादन बढ़ने से न केवल स्थानीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि यह गांवों में एक स्वस्थ, ऊर्जावान और कार्यकुशल कार्यबल का निर्माण करता है। इस प्रकार, डेयरी व्यवसाय सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि या आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और कुपोषण मुक्त राष्ट्र के सपने को साकार करने की एक मजबूत आधारशिला है।

कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरणः

सतत ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कृषि तथा पशुपालन का एकीकृत होना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की मांग है। आधुनिक समय में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग के कारण कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ शक्ति तेजी से घट रही है, मिट्टी की जैविक संरचना नष्ट हो रही है, और भूजल प्रदूषित हो रहा है। इस गंभीर पारिस्थितिक संकट के बीच, डेयरी क्षेत्र जैव–उर्वरक यानी गोबर और गोमूत्र की खाद का सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत बनकर उभरता है। खेतों में पारंपरिक गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद) और जीवामृत का उपयोग करने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। यह न केवल मृदा स्वास्थ्य और उसकी जल धारण क्षमता को बनाए रखता है,

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-5(A)| May-2026

बल्कि फसलों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर रासायनिक खादों पर किसानों की निर्भरता और लागत को भी भारी मात्रा में कम करता है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत कृषि और पशुपालन के बीच एक मजबूत सहजीवी संबंध स्थापित होता है। फसलों की कटाई के बाद बचने वाले कृषि अवशेष, जैसे– धान और गेहूं का भूसा, मक्के के डंठल और अन्य सूखी पराली, पशुओं के लिए एक बेहतरीन और पौष्टिक चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन की एक बहुत बड़ी समस्या का प्राकृतिक समाधान करती है।

सहकारिता का महत्व और तकनीकी उन्नतिः

भारत की ऐतिहासिक श्वेत क्रांति ने विश्व के समक्ष यह अकाट्य उदाहरण प्रस्तुत किया कि सहकारिता के माध्यम से किस प्रकार समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े छोटे और सीमांत दुग्ध उत्पादकों को संगठित करके बाजार की बड़ी और प्रतिस्पर्धी ताकतों के समकक्ष खड़ा किया जा सकता है। पारंपरिक डेयरी व्यवसाय में निजी व्यापारियों और बिचौलियों का बोलबाला था, जो किसानों का आर्थिक शोषण करते थे और उन्हें दूध का बेहद कम मूल्य देते थे। सहकारी समितियों के त्रि–स्तरीय ढांचे (गांव, जिला और राज्य स्तर) ने इन बिचौलियों की कड़ियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का एक बड़ा और उचित हिस्सा सीधे दूध उत्पादक किसानों की जेब में पहुंचने लगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत हुई।

समकालीन युग में, सहकारिता के इस सुदृढ़ ढांचे को आधुनिक तकनीकों के समावेशन ने एक नई और वैज्ञानिक दिशा प्रदान की है। तकनीकी उन्नति का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर पड़ा है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों और सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की सुविधा से दूध का तौल होते ही उसकी शुद्धता के आधार पर सटीक मूल्य की गणना कंप्यूटर द्वारा तुरंत हो जाती है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में बिना किसी देरी या कटौती के जमा कर दी जाती है। इस पारदर्शिता ने पूरी व्यवस्था में किसानों के भरोसे को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक समय में पशु प्रबंधन के लिए आईओटी आधारित स्मार्ट टैग, एआई संचालित स्वास्थ्य निगरानी उपकरण और दुग्ध प्रसंस्करण की स्वचालित मशीनरी का उपयोग बढ़ रहा है। ये सभी तकनीकी प्रगति न केवल दूध की गुणवत्ता और वैश्विक मानकों को सुनिश्चित कर रही हैं, बल्कि डेयरी क्षेत्र को एक अत्यधिक लाभकारी, आधुनिक और सतत व्यवसाय के रूप में स्थापित कर रही हैं।

भारतीय डेयरी क्षेत्र जहाँ एक ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे कई गंभीर और उभरती हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में सबसे बड़ा संकट जलवायु परिवर्तन का है। बढ़ते तापमान और अनिश्चित मानसूनी चक्र के कारण दुधारू पशु गंभीर हीट स्ट्रेस (गर्मी के तनाव) से गुजरते हैं, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, देश में हरे और सूखे चारे की भारी कमी बनी हुई है, क्योंकि चारागाह भूमि लगातार घट रही है। पशुओं में फैलने वाली संक्रामक महामारियां, जैसे कुछ समय पहले आया लम्पी स्किन डिजीज एवं फुट–एंड–माउथ डिजीज न केवल पशुओं की जान लेती हैं बल्कि किसानों को भारी वित्तीय संकट में डाल देती हैं। ग्रामीण अंचलों में आज भी समय पर और गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाओं, एम्बुलेंस नेटवर्क तथा कुशल डॉक्टरों का अभाव है, जिसके कारण छोटे पशुपालक प्राथमिक स्तर पर ही हार मान लेते हैं। इन चुनौतियों से निपटने और डेयरी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक बहुआयामी और दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

निष्कर्षः

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि डेयरी क्षेत्र केवल दूध उत्पादन का जरिया नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की प्रगति का इंजन है। यह गरीबी उन्मूलन, पोषण वृद्धि, महिला आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को एक साथ साधने की क्षमता रखता है। यदि उचित नीतिगत समर्थन, बेहतर बुनियादी ढांचा और आधुनिक तकनीक का समन्वय हो, तो डेयरी क्षेत्र भारत के गाँवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में सबसे निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वास्तविक अर्थों में, सतत ग्रामीण विकास का मार्ग गौशालाओं और डेयरी समितियों से होकर ही गुजरता है।

संदर्भ स्रोतः

1. गौतम, डॉ. एन. के. (2018), भारतीय डेयरी क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 87
2. यादव, डॉ. बी. पी. (2017) डेयरी क्षेत्रः भारत के गाँवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में निर्णायक, शैक्षिक प्रकाशन, बहड़ोर, राजस्थान, पृ. 65
3. सिंह, डॉ. के. एन. (2019) सहकारिता का महत्व और तकनीकी उन्नति, नवनीत प्रकाशन, सागर, पृ. 128
4. ठाकुर, दिव्या (2016) डेयरी क्षेत्रः आर्थिक सुदृढ़िकरण और आय का स्रोत, सीरीयल्स पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 49
5. रॉय, एम. के. (2014), भारत में डेयरी क्षेत्र के बदलते स्वरूप, मोतिलाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. शर्मा, डॉ. डी.. एन. (2014), भारत में डेयरी क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां, न्यू सिरियल पब्लिकेशन प्रा. लि., पृ. 84
7. वार्षिक प्रतिवेदन (2024–25) डेयरी विकास निदेशालय, नई दिल्ली, पृ. 105